देशभर में लगाए जाएंगे ईवी के लिए 72 हजार फास्ट चार्जिंग स्टेशन

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अगले 15 महीनों में देशभर में 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इनमें 48,400 चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया के लिए जबकि 22,100 स्टेशन इलेक्ट्रिक कार के लिए लगाए जाएंगे। ट्रक और बस के लिए हाईवे पर 1,800 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार के फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए उन 40 शहरों का चयन किया गया है, जहां इनकी हिस्सेदारी सड़कों पर दिखने लगी है। ट्रक व बस के हाईवे और कारिडोर की भी पहचान की गई है। इन पर बस व ट्रक काफी अधिक संख्या में चलते हैं।

पीएम ई-ड्राइव के तहत अगले 15 महीनों में की जाएगी स्थापना, इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग स्टेशन के लिए 40 शहरों का चयन

कार के लिए चयनित शहर

दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, लुधियाना, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर, नागपुर और देहरादून

इस वर्ष सड़कों पर दिख सकता है ई-ट्रक

देश में दोपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत के पास पहुंचने वाली है, जबकि वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री वर्ष 2023 की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 99,000 यूनिट तक पहुंच गई। इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक ट्रक भी सड़क पर दिखने के आसार हैं। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

इन हाईवे पर लगेंगे स्टेशन	
दिल्ली	आगरा
दिल्ली	लखनऊ
दिल्ली	जयपुर
इंदौर	भोपाल
दिल्ली	देहरादून
दिल्ली	मनाली
दिल्ली	अमृतसर

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। इस मद में 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई यह स्कीम मार्च 2026 तक मान्य रहेगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं।

लक्ष्य को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे काम : फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। राज्य स्थानीय निकायों की मदद से अपने यहां चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह आवंटन की पहचान के साथ अन्य नियम तय करेंगे। बिजली मंत्रालय राज्य के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पंजाब और बंगाल जैसे कुछ राज्यों के शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए नियम बनाकर टेंडर भी जारी कर दिया किया गया है।

फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए सबसे जरूरी चीज जगह है। मंत्रालय के मुताबिक शहर में कार चार्जिंग के लिए 60 वर्गमीटर तक की जगह की जरूरत होगी। वहीं बस के लिए 300 वर्गमीटर की जरूरत होगी। 40-60 वर्गमीटर की जगह में दोपहिया व तिपहिया का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकता है।